

तिरोड़ा : एक व 2 रु. के सिक्कों को लेकर परेशानी बढ़ गई है. दुकानदार व बैंक यह सिक्के लेने में मना कर रहे हैं. उसे लेकर ग्राहक-दुकानदार के बीच व बैंक कर्मियों से विवाद होने लगाता है. बैंक और व्यापारी सिक्के को स्वीकार करने से इंकार कर रहे हैं. मजदूर, ठेकेदार, व्यापारी, किसान मजदूरों को नोट के बदले सिक्के दिए जाते हैं. मजदूर वर्ग के साथ-साथ कर्मचारी जरूरी सामान लेने के लिए चिल्लर एक, दो, पांच, दस रु. का सिक्का देने की कोशिश करते हैं. लेकिन 1 व 2 रु. के सिक्के लेने से इंकार कर देते हैं.

संक्षिप्त

स्पीड ब्रेकर बन रहे हादसों की वजह

गोंदिया : स्पीड ब्रेकर हादसों में कमी लाने के लिए सड़कों पर बनाए जाते हैं लेकिन अगर यह स्पीड ब्रेकर औसत से ऊंचा हो तो यह हादसों का भी सबब बन जाता है. शहर में कई ऐसे स्पीड ब्रेकर हैं जो औसत से ऊंचे हैं. कई जगहों पर स्पीड ब्रेकरों पर बाइक चालक अगर जरा सी असावधानी बरतेंगे तो हादसे का शिकार हो सकते हैं.

मोबाइल नेटवर्क से उपभोक्ता परेशान

सालेकसा : ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या से उपभोक्ता परेशान हैं. क्षेत्र में सभी कंपनियों द्वारा जहां एक तरफ उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए लिए लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ सभी कंपनियों के मोबाइल नेटवर्क ध्वस्त होने से उपभोक्ता अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं.

ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात की मौत

गोंदिया : रावणवाड़ी थाने के तहत गात्रा-बघोली रेलवे मार्ग पर पोल क्र. 1015/10 के पास ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई. फियादी प्रबंधक जीवनलाल देवांगन की शिकायत पर रावणवाड़ी पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है. जांच सहायक पुलिस निरीक्षक अर्जुन राठोड कर रहे हैं.

स्वच्छ भारत अभियान की उड़ रही धज्जियां

आमगांव : तहसील के अन्य ग्रामों के लोग स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं. कई ग्रामीण घर में शौचालय होते हुए भी शौच के लिए बाहर जाते हैं. साथ ही शासन की शौचालय योजना का लाभ लेकर अनेकों ने आधा अधूरा काम किया है. खुले में शौच करने वालों पर कार्रवाई करने वाली गुडमॉर्निंग टीम नदारद हो गई है.

छात्रावास से 18,200 रु. का माल चोरी

गोंदिया : सालेकसा थाने के तहत ग्राम आमगांव खुर्द में स्थित बंद पड़े नेताजी सुभाषचंद्र बोस निवासी छात्रावास के रसोई कक्ष के दरवाजे की कुंडी खोलकर अज्ञात व्यक्ति ने 18 हजार 200 रु. का माल चुरा लिया. आमगांव निवासी फियादी धनराज बिजलाल पटले (57) की शिकायत पर आमगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है. जांच हवालदार वैद्य कर रहे हैं.

बीमारी से हुई मौत

गोंदिया : अर्जुनी मोरगांव थाने के तहत बुढाई रेली (प्रतापगढ़ पहाड़ी) पर भिवखिड़की निवासी विजय तुलसीराम दुधुरे (56) पुजारी का काम करता था. उसे कुछ दिनों से खांसी की बीमारी थी. इसी बीच प्रतापगढ़ पहाड़ी मुख्य शिवमंदिर में उसका शव मिला.

तीन राज्यों से पर्यटकों का बढ़ता प्रवाह

सालेकसा बना बारिश के पर्यटन का नया केंद्र !

संवाददाता / गोंदिया बारिश की फुहारों ने पर्वत श्रृंखलाओं को हरियाली की चादर ओढ़ा दी और लगातार बहते जलप्रपात से हाजराफॉल का रूप और भी निखर गया। इसलिए सालेकसा तालुका स्थित हाजराफोल की ओर पर्यटकों के कदम बड़ी संख्या में मुड़ने लगे हैं। महाराष्ट्र के साथ मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ से पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं, बारिश के मौसम में यह प्राकृतिक स्थल तीन राज्यों के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है।



बारिश के मौसम में हाजराफॉल क्षेत्र का प्राकृतिक रूप अक्षरशः बदल जाता है। पहाड़ों की ढलानों से तेजी से गिरता पानी, उसकी लगातार कानों पर पड़ने वाली गूंज, घनी हरियाली और धुंध की हल्की चादर के कारण क्षेत्र को मनोहारी रूप प्राप्त होता है। इसलिए शनिवार-रविवार के साथ ही

सुविधाओं के साथ सुरक्षा पर जोर होना चाहिए

हाजराफॉल का पर्यटन विकास करते समय प्रकृति का संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, सुरक्षित कठड़े, वाहनतल, पीने का पानी, शौचालय, दिशासूचक फलक और आपातकालीन सहायता जैसी बुनियादी सुविधाओं को सक्षम करने की आवश्यकता है। बरसात में पानी का प्रवाह बढ़ने के कारण पर्यटकों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय आवश्यक हैं। प्रकृति ने मुक्तहस्त से बिखरी सुंदरता के कारण हाजराफॉल को पर्यटन की बड़ी क्षमता प्राप्त हुई है। उचित प्रचार, सुविधाओं और नियोजन का साथ मिलने पर यह स्थल विदर्भ के महत्वपूर्ण प्रकृति-पर्यटन केंद्र के रूप में निश्चित रूप से प्रसिद्धि पा सकता है।

सर्वजनिक छुट्टी के दिनों में पर्यटकों की भीड़ विशेष रूप से बढ़ती हुई दिखाई देती

है। परिवार, मित्रमंडली और प्रकृतिप्रेमियों द्वारा इस स्थान को पसंद किया जा रहा है।

गोंदिया जिले की भौगोलिक स्थिति मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़ी होने के कारण हाजराफॉल तक इन दोनों पड़ोसी राज्यों के पर्यटकों के लिए भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। कम दूरी में प्रकृति का भरपूर आनंद लिया जा सकता है, इसलिए इस स्थान की लोकप्रियता बढ़ रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी क्षेत्र के प्राकृतिक दृश्यों की जानकारी बढ़े पैमाने पर प्रसारित हो रही है, जिससे नए पर्यटकों का आकर्षण बढ़ने की संभावना है।

ग्रामीण ZP शालाओं को मिले 4 4 5 शिक्षक

विद्यार्थियों को मिलेगी बड़ी राहत, पवित्र पोर्टल के पहले चरण में नियुक्ति

संवाददाता / गोंदिया

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूलों में लंबे समय से बनी शिक्षकों की कमी अब दूर होने के संकेत मिल रहे हैं. पवित्र पोर्टल के माध्यम से पहले चरण में 445 शिक्षक गोंदिया जिला परिषद को उपलब्ध हुए हैं. इन शिक्षकों की जल्द ही दस्तावेज जांच और समुपदेशन प्रक्रिया पूरी कर रिक्त पदों वाली स्कूलों में नियुक्ति की जाएगी. अधिकारियों के अनुसार, 10 सितंबर तक इन शिक्षकों के स्कूलों में कार्यभार संभालने की संभावना है. इसके बाद जिले में शिक्षकों के करीब 185 पद रिक्त रहेंगे, जिन्हें दूसरे चरण में भरने की उम्मीद है. जिला परिषद के अंतर्गत शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों की जानकारी शासन को भेजी गई



थी.

इसके अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के उपशिक्षक तथा स्नातक शिक्षक पदों के लिए पवित्र पोर्टल के माध्यम से उम्मीदवार उपलब्ध हुए हैं. जिला परिषद ने प्राथमिक बंगाली माध्यम के 5, हिंदी माध्यम के 95, मराठी माध्यम के 478 तथा माध्यमिक मराठी माध्यम के 50 इस तरह कुल 628 रिक्त पदों का प्रस्ताव शासन को

काफी कम होगी. इसका सीधा लाभ जिले के 60 हजार से अधिक विद्यार्थियों को मिलने की उम्मीद है.

एक शिक्षक के भरोसे चल रही अथवा शिक्षकों की कमी से जूझ रही स्कूलों में नियमित कक्षाएं संचालित करने में मदद मिलेगी. इससे विद्यार्थियों के शैक्षणिक नुकसान को रोकने के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आने की संभावना है. जिले में कुल 628 शिक्षक पद रिक्त थे. इनमें से 445 पदों के लिए शिक्षक उपलब्ध हो गए हैं. अब शेष 185 रिक्त पदों को दूसरे चरण में पवित्र पोर्टल के माध्यम से भरने की उम्मीद जताई जा रही है. यदि ये पद भी भर जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूलों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी.

तिरोड़ा में स्वामी श्री राजेंद्रदास देवाचार्यजी महाराज का आगमन



संवाददाता / तिरोड़ा

वृंदावन के मूलक पीठ एवं राजस्थान के रायवासा अग्रपीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी श्री राजेंद्रदास देवाचार्यजी महाराज का संतों सहित तिरोड़ा आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने रावत परिवार के निवास पर सदरिच्छा भेंट की। संतों के आगमन पर प्रणव रावत एवं उनके परिवारजनों ने श्रद्धापूर्वक स्वागत एवं सम्मान किया। संतों के दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नगर के अनेक गणमान्य नागरिक, व्यापारी, जनप्रतिनिधि, चिकित्सक,

शिक्षक एवं पत्रकार रावत परिवार के निवास पर पहुंचे। इस अवसर पर नागपुर से सुनील रावत, वर्धा से अनिल रावत, होशंगाबाद से कपिल रिछारिया तथा तिरोड़ा से वैभव रावत, विशाल रावत, राम रावत सहित रावत परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।

प्रसिद्ध संतों के तिरोड़ा आगमन से नगर में श्रद्धा एवं उत्साह का वातावरण रहा। बड़ी संख्या में नागरिकों ने संतों के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में तिरोड़ा गजानन महाराज राम मंदिर समिति के प्रमुख रमेशचंद्र

केशरवानी, प्रसिद्ध व्यापारी राजेंद्र केशरवानी, पूर्व नगराध्यक्ष एवं वर्तमान पार्षद अजय गौर, पूर्व नगराध्यक्ष एवं बैंक संचालक डॉ. अविनाश जायसवाल, पूर्व नगरसेवक रामकुमार असादी, अनिल असादी, सुनील असादी, संतोष असादी, शालिग्राम असादी, डॉ.

मनीष दुबे, विद्यालय के प्राचार्य निकेश मिश्रा, वरिष्ठ शिक्षक दिलीप झरारिया, वरिष्ठ पत्रकार दीपक कुमार जायसवाल, धनंजय पंचारिया, संदीप तिवारी, पंडित महेंद्र तिवारी, राजू मिश्रा, राशु केशरवानी, तिवारी एवं सोनू शर्मा सहित अनेक नागरिक उपस्थित थे। संतों के व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद तिरोड़ा आगमन पर नगरवासियों ने प्रसन्नता व्यक्त की। संतों के दर्शन एवं आशीर्वाद का अवसर उपलब्ध कराने के लिए नागरिकों ने रावत परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया।

स्वच्छता प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है : बडोले

स्वर्गरथ और सेप्टिक टैंक सक्शन टैंकर का किया लोकार्पण

संवाददाता / सड़क अर्जुनी

स्वच्छता केवल नगर पंचायत की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। नागरिकों को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं द्वारा आधुनिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना आवश्यक है।

यह उद्घार विधायक राजकुमार बडोले ने व्यक्त किए। स्थानीय नगर पंचायत के माध्यम से नागरिकों को बेहतर और तत्पर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वर्गरथ तथा सेप्टिक टैंक सक्शन वाहन का लोकार्पण विधायक



राजकुमार बडोले के हाथों गुरुवार, 27 अगस्त को किया गया। इस मौके पर वे बोल रहे थे। विधायक बडोले ने कहा, स्वर्गरथ के माध्यम से अंतिम संस्कार के समय नागरिकों को बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी, वहीं सेप्टिक टैंक सक्शन वाहन के कारण गंदे पानी

एवं सेप्टिक टैंक की सफाई से जुड़ी समस्याओं का अधिक आसानी से समाधान किया जा सकेगा। उन्होंने आगे कहा कि स्वच्छता, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, सड़क तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए सड़क अर्जुनी शहर का नियोजनबद्ध विकास

करने के लिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए।

साथ ही उन्होंने नागरिकों से भी स्वच्छता बनाए रखने के लिए नगर पंचायत को सहयोग करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में नप अध्यक्ष तेजराम मडावी, उपाध्यक्ष वंदना डोंगरवार, पंस सभापति चेतन वडगाये, नप सभापति शाहिस्ता शेख, कमला अग्रवाल, सायमा शेख, मुख्याधिकारी सरंश खंडेकर, पार्षद देवचंद्र तरोने, महेंद्र वंजारी, अंकित भंडारकर, अमलेश अंबादे तथा कूडबास सभापति डॉ. अविनाश काशिवार सहित नगर पंचायत के कर्मचारी व नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

नौनिहालों की किस्मत में कीचड़ भरी राह

कोहलीटोला की गंभीर समस्या

संवाददाता / सड़क अर्जुनी

तहसील के कोहलीटोला गांव में स्कूली बच्चों को बारिश के दिनों में कीचड़ भरे रास्ते से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है। पक्की सड़क के अभाव में विद्यार्थियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है. इसके बावजूद अब तक जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की ओर से समस्या का समाधान नहीं किया गया है. पालकों व विद्यार्थियों ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द पक्की सड़क का निर्माण कराने की मांग की है.

पंचायत समिति अंतर्गत चिखली गट ग्राम पंचायत में आने वाले कोहलीटोला की आबादी करीब दो हजार है. गांव 0 निजी संस्था द्वारा पहली से आठवीं कक्षा तक विद्यालय संचालित हैं. कोहलीटोला मुख्य गांव दो हिस्सों में बंटा हुआ है. एक हिस्से में ग्रामीण सश्रीकरण नदी के किनारे ऊंचाई वाले क्षेत्र में वर्षों से निवास कर रहे हैं. स्वतंत्रता के 80 वर्ष बाद भी इस बस्ती को मुख्य गांव से



जोड़ने वाली पक्की सड़क नहीं बन सकी है. आज भी ग्रामीणों को आवागमन के लिए पुराने कच्चे रास्ते का सहारा लेना पड़ता है. बारिश के मौसम में यही रास्ता कीचड़ से भर जाता है, जिससे बस्ती का संपर्क लगभग टूट जाता है. विद्यार्थियों के साथ ही ग्रामीणों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी परेशानी झेलनी पड़ती है. एक ओर सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्कूल, बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाओं पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर कोहलीटोला के बच्चों को बरसात में कीचड़ से होकर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है.

प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना में स्कूलों को FBO लाइसेंस से मुक्त किया जाए

गोंदिया जिला माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य संघ ने शिक्षाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

संवाददाता / तिरोड़ा प्रधानमंत्री पोषण आहार शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत विद्यालयों के लिए एफबीओ (फूड बिजनेस ऑपरेटर) पंजीकरण एवं लाइसेंस अनिवार्य किए जाने के निर्णय का गोंदिया जिला माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य संघ ने विरोध किया है। इस संबंध में संघ की ओर से विभिन्न मांगों का ज्ञापन जिला माध्यमिक शिक्षाधिकारी के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भेजा गया। संघ का कहना है कि प्रधानाचार्य खाद्य व्यवसाय करने वाले व्यवसायी अथवा खाद्य व्यवसाय के संचालक नहीं हैं, बल्कि वे शैक्षणिक संस्थाओं के

प्रशासनिक प्रमुख हैं। इसलिए उन पर खाद्य व्यवसाय संचालक के रूप में पंजीकरण अथवा लाइसेंस लेने की जिम्मेदारी डालना उचित नहीं है।

जिलाध्यक्ष धनराज हुकरे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने यह ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर विदर्भ संगठन सचिव एवं प्राचार्य डी. आर. गिरीपुंजे, जिला कार्याध्यक्ष अशोक बिसेन, संदीप मांडरे, पूर्व जिलाध्यक्ष डी. आर. पटले, विदर्भ महिला प्रतिनिधि रजिया शेख, विदर्भ प्रतिनिधि दिनेश बहेकार, एम. आर. राऊत, एम. एम. मेश्राम, एस. डी. बघेले, आई. वी. गभने, विनोद गिरेपुंजे, एम. यू. ठाकुर, आर. वाय. कटरे, आर.



एच. तनवाणी, महेंद्र मेश्राम, पी. सी. रहांगडाले, सी. सी. वाघाडे तथा एस. आर. रहांगडाले प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस दौरान विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक समस्याओं पर चर्चा कर शिक्षाधिकारी सुधीर महामुनी के समक्ष समस्याएं रखी गईं। उन्होंने

पंजीकरण एवं लाइसेंस अनिवार्य नहीं किया जाए। आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा 28 जुलाई 2026 को जारी आदेश में विद्यालयों पर लागू होने वाले प्राधान्यों पर पुनर्विचार कर स्कूलों को इसके दायरे से बाहर रखा जाए। संघ ने यह भी मांग की कि विद्यालयों को एफबीओ पंजीकरण के दायरे में लाने के बजाय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं सुरक्षा की जांच के लिए संबंधित सरकारी विभाग के माध्यम से स्वतंत्र और प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। इससे साथ ही प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों पर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त कानूनी अथवा प्रशासनिक

जिम्मेदारी नहीं डाली जाए। इस विषय पर स्कूल शिक्षा विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग तथा संबंधित सभी विभागों की संयुक्त बैठक आयोजित कर स्पष्ट शासन निर्णय एवं परिपत्र जारी करने की मांग भी की गई। संघ ने कहा कि प्रधानमंत्री पोषण आहार शक्ति निर्माण योजना एक सरकारी कल्याणकारी योजना है। इसलिए इसके क्रियान्वयन से संबंधित प्रशासनिक जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से संबंधित सरकारी विभागों एवं अधिकारियों के बीच विभाजित की जानी चाहिए, ताकि प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों पर अनावश्यक अतिरिक्त दायित्व न डाला जाए।

संपादकीय

बिना हुनर के डिग्री

नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट हमारे नीति-नियंताओं को आईना दिखाने वाली है। चौंकाने वाली ये रिपोर्ट बताती है कि देश में नब्बे फीसदी से अधिक स्नातकऐसी नौकरियां कर रहे हैं, जिसका उनकी डिग्री से कोई संबंध नहीं होता है। जाहिरा तौर पर यह आंकड़ा हमारी शिक्षा व्यवस्था की विसंगतियों को ही उजागर करता है। इसके मायने हैं कि आज भी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में ऐसी शिक्षा दी जा रही है, जो मौजूदा आर्थिकी से नहीं जोड़ती। देश-दुनिया का मौजूदा आर्थिक परिदृश्य बिल्कुल बदल चुका है। सरकारी नौकरियां ना के बराबर हैं, मगर हर स्नातक उसके लिये आवेदन करता है। जबकि रोजगार बाजार में उतरने के लिये युवाओं के पास कौशल विकास, व्यावहारिक दक्षता, तकनीकी ज्ञान और कुशल प्रबंधन का अनुभव होना जरूरी है। दरअसल, अधिकांश शिक्षण संस्थानों में आज भी वर्षा पुराना वह पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है जो मौजूदा प्रतियस्धी समय में रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी नहीं देता। इसके लिये जरूरी है कि युवाओं को उद्योग, बाजार व व्यावसायिक संस्थानों की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा दी जाए। लेकिन विडंबना यह है कि तीन-चार साल के अध्ययन के बाद छात्रों को जो डिग्री मिलती है, वह उन्हें रोजगार के बाजार में कदमताल करने का हुनर नहीं देती। यह तभी संभव है जब हमारी शिक्षा, कौशल विकास व अर्थव्यवस्था में तारतम्य स्थापित हो सकेगा। लेकिन हर साल लाखों बीए, एम.ए. व अन्य मानविकीय विषयों की डिग्री हासिल करने वाले बेरोजगारों की पंक्ति में शामिल हो जाते हैं। यही वजह है कि देश में स्नातक बेरोजगारों का प्रतिशत देश की सामान्य बेरोजगारी दर से कहीं अधिक है। महिला स्नातकों की दर तो पुरुष स्नातकों से भी कहीं ज्यादा है। ऐसे में उस उच्च शिक्षा का क्या औचित्य जो युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती। असल में, बदलते वक्त के अनुरूप युवाओं की शिक्षा में जो जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए थे, वे अभी तक सिरिं नई चढ़ पाये हैं।

दरअसल, हर युवा में कला-कौशल का एक विशिष्ट गुण होता है। उसका मूलभूत रूझान एक विशेष क्षेत्र में होता है। लेकिन इस गुण को न तो अभिभावक समझ पाते हैं और न ही शिक्षक। छात्र भेड़चाल में आकर शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेते हैं। लेकिन यह उनकी रुचि का विषय नहीं होता है। कई अध्ययन बताते हैं कि अपनी रुचि के विषय में युवा बेहतर कार्य प्रदर्शन करते हैं। यह संभव नहीं कि हर छात्र डॉक्टर व इंजीनियर ही बने। लेकिन समाज में ऐसा करने की होड़ बनी हुई है। एक समय बैंकिंग, रेलवे आदि में भविष्य तलाशने की होड़ लगी। पिछले कुछ समय में कंप्यूटर साईंस में इंजीनियरिंग करने का फैशन चला। वैश्विक स्थितियों में बदलाव व एआई के वर्चस्व के चलते अचानक कंप्यूटर साईंस के क्षेत्र में नौकरियों में तेजी से कटौती हुई। लेकिन देश में हजारों शिक्षण संस्थान आज भी इस भेड़चाल में युवाओं को धकेल रहे हैं। विडंबना यह है कि हमारे नीति-नियंताओं ने दूरदर्शी दृष्टिकोण न अपनाते हुए, भविष्य की दीवार पर लिखी इबारत को नहीं पढ़ा। यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं का देश होने के बावजूद हम इस जनसांख्यिकीय लाभ उठाने में विफल रहे हैं। हमारे उद्योगों ने भी अपनी जरूरत के मुताबिक युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिये इस बाबत चलाये जा रहे कार्यक्रमों में सहयोग नहीं किया। यही वजह है कि आज देश में कामचलाउ इंटरशिप व अप्रेंटिसशिप का बोलबाला है। यदि हमारा निजी क्षेत्र इस दिशा में रचनात्मक पहल करता तो उसे बड़ी संख्या में अपनी जरूरतों के मुताबिक युवा प्रतिभाएं मिल सकती थीं। इसे दिशा देने में देश की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं आईआईटी व आईआईएम की बड़ी भूमिका हो सकती थी। याद रहे कि कौशल विकास का मालब केवल एक सार्टिफिकेट हासिल करना नहीं है। देश को कौशल विकास से लैस युवाओं की जरूरत है। जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिये अनिवार्य शर्त भी है। नीति-नियंताओं को इस मामले में चीन की औद्योगिक व तकनीकी क्रांति से जुड़ी नीतियों से सीखने की आवश्यकता है। जरूरत इस बात की है कि हमारे स्कूल-कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालयों तक में रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रमों को तरजीह दी जाए।

मनपा टाउन हॉल के लिए दशहरे तक की डेडलाइन

नागपुर : महाल में निर्माणाधीन श्रीमंत रघुजी राजे भोसले टाउन हॉल का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश शुक्रवार को महापौर नीता ठाकरे ने अधिकारियों और ठेकेदार को दिए. उन्होंने नई डेडलाइन तय करतें हुए कहा कि दशहरे तक किसी भी हाल में टाउन हॉल का निर्माण पूरा हो जाना चाहिए. अक्तूबर महीने में इस बार दशहरा आ रहा है.

शुक्रवार को स्थायी समिति कक्ष में महापौर ठाकरे ने बैठक लेकर टाउन हॉल के निर्माण कार्य की समीक्षा की. बैठक में स्थायी समिति सभापति शिवानी दाणी, सत्तापक्ष नेता बाब्या बोरकर, मुख्य अभियंता लीना उपाध्याय, अधीक्षक अभियंता विजय गुन्बक्षणी, कार्यकारी अभियंता अश्विनी येसूचेटवार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.

महापौर नीता ठाकरे ने टाउन हॉल के निर्माण कार्य की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि टाउन हॉल की ध्वनि

228 सदस्यों के लिए बैठने की व्यवस्था

6808.08 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नए टाउन हॉल का निर्माण किया जा रहा है. इस पर लगभग 125.75 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं. नए टाउन हॉल की दूसरी मंजिल पर 1621.28 वर्ग मीटर क्षेत्र में 228 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी. इसके अलावा सभागृह में 50 अधिकारियों के लिए भी आसन व्यवस्था की गई है. इस मंजिल पर महापौर, आयुक्त, उपमहापौर, विपक्ष के नेता तथा उनके कार्यालयों के लिए कक्ष प्रस्तावित हैं. 1610.48 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली तीसरी मंजिल पर आगतुकों और 210 लोगों के लिए गैलरी बनाई जाएगी. वहीं 1658 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली चौथी मंजिल पर कार्यालय, कैंटीन और टैरेस की व्यवस्था होगी.



व्यवस्था नई संसद भवन की तरह अत्याधुनिक होनी चाहिए. ध्वनि व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने के अतिरिक्त कार्य के लिए हफीज कॉन्ट्रैक्टर की ओर से दो विशेषज्ञ उपलब्ध कराने तथा काम में तेजी

लाने के निर्देश महापौर नीता ठाकरे ने दिए.

महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर शनिवार को टाउन हॉल के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे. इस दौरान वे कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे. वर्तमान में टाउन हॉल का मुख्य निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. हालांकि फर्नीचर, ध्वनि व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था सहित कई छोटे-मोटे कार्य अभी बाकी हैं.

धामणगांव रेलवे (अमरावती) : विविध लंबित मांगों के लिए अमरावती से यवतमाल की ओर निकले आदिवासी छात्रों के ‘लांग मार्च’ आंदोलन ने राज्य प्रशासन की नींद उड़ा दी. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके के यवतमाल स्थित आवास को घेरने के लिए निकला यह मोर्चा रोकने के लिए स्वयं मंत्री को आधी रात को मैदान में उतरना पड़ा. शुक्रवार, २८ अगस्त की रात करीब १२ बजे डॉ. अशोक उईके बाभुलगांव पहुंचे और आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात की. शनिवार को तड़के ३ बजे तक चली बैठक में सकारात्मक हल निकला और आंदोलन फिलहाल स्थगित करने का निर्णय छात्र प्रतिनिधियों ने लिया है.

१ सितंबर को सीएम के साथ बैठक : आदिवासी छात्रों की महत्वपूर्ण मांगों पर



सकारात्मक समाधान निकालने के लिए अब सीधे मंत्रालय में गतिविधियां शुरू हो गई हैं. १ सितंबर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुंबई में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया है. इसमें आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके, अपर

आयुक्त संदीप गोलाइट, आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधि और संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे.

बाभुलगांव में हुआ आधी रात को ‘मथन’

३ पिस्तौल, २ कारतूस के साथ धराया थापा

भांडेवाड़ी फायरिंग की जांच में खुला सुराग, जरीपटका में कार्रवाई

संवाददाता । नागपुर

क्राइम ब्रांच यूनिट-५ की टीम ने जरीपटका थापा क्षेत्र में जाल बिछाकर मेकोसाबाग, लुंबिनीनगर निवासी कुख्यात अपराधी आकाश राजन थापा (२९) को ३ देसी पिस्तौल और २ जिंदा कारतूसों के साथ धर दबोचा. पुलिस ने उसके पास से कुल १.५७ लाख रुपए का माल जब्त किया है. भांडेवाड़ी गोलीबारी मामले में संदेहस्पद और रिकॉर्ड पर दर्ज आरोपियों की तलाश के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली आकाश थापा मेकोसाबाग स्थित लैंडी मैदान, मातृछाया वाचनालय के पास नागरिकों को हथियार दिखाकर धमका रहा है. पुलिस टीम ने तुरंत



घेराबंदी कर उसे हिरासत में लिया. उसकी तलाशी लेने पर २ स्टील मैगजीन वाली देसी पिस्तौल, २ जिंदा कारतूस और २ मोबाइल मिले. बाद में उसके घर की तलाशी के दौरान १ अन्य स्टील मैगजीन वाली पिस्तौल और १

देसी कट्टा बरामद हुआ.

पूछताछ में आकाश थापा ने कबूल किया कि ये हथियार उसके साथी योगेश सीरिया (सदर) ने मध्य प्रदेश के खंडवा निवासी आकाश भाई से मंगवाए थे. कुछ दिन पहले सेंट्रल जेल

से रिहा हुए कुख्यात अपराधी विशाल समुद्रे व अन्य को लेने आए उसके साथी कुणाल समुद्रे व अन्य को धमकाने के लिए आकाश थापा, गवलीपुरा, सदर निवासी योगेश सीरिया और गिड्डीखदान निवासी अभय ने हथियारों का प्रदर्शन किया था. पुलिस ने आर्म्स एक्ट और महाराष्ट्र पुलिस कानून के तहत मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटिल, सहआयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, अपर आयुक्त (क्राइम) राजेंद्र दाभाड़े, डीसीपी दीपक अग्रवाल और एसीपी वैभव जाधव के मार्गदर्शन में पीआई विनायक गोले, एपीआई गणेश कदम, पीएसआई विशाल सांगोले व यूनिट-५ की टीम ने की.

नेपाल से लौटें ३ महिलाएं, सीएम का आभार माना

वर्धा : नेपाल में आई बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच फंसे भारतीय पर्यटक अब लौटने लगे हैं. इसी क्रम में काठमांडू से उड़ान भरा चार सदस्यीय दल दिल्ली पहुंचा और वहां से रेल मार्ग से सुरक्षित रूप से नागपुर तक पहुंचा. इन चार में वर्धा जिले के सेलू तहसील के चार मंडल गांव निवासी सुलोचना खापरे, उनकी बहन नागपुर निवासी इंदिरा चौधरी और सहेली वर्षा उपाध्याय भी शामिल थीं.

तीनों शनिवार को सुबह नागपुर पहुंचकर अपने-अपने घर सुरक्षित लौट गईं. सुलोचना खापरे ने नेपाल यात्रा के अनुभव साझा करते हुए बताया, ‘हम काठमांडू में ठहरे हुए थे और आसपास के इलाकों में घूमने निकले थे. हमने पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन भी किए. शुरू में हमें वहां की बाढ़ की गंभीरता का पता नहीं चला. भारत से फोन आने पर ही स्थिति का आभास हुआ और

परिवार की चिंता बढ़ी. ‘उन्होंने बताया कि परिवार की तरफ से बार-बार कॉल आने पर और स्थिति की जानकारी मिलते ही चारों ने तात्कालिक रूप से भारत वापसी का निर्णय लिया. एक पर्यटक की अचानक तबीयत खराब होने के कारण समूह ने सड़क मार्ग से लौटने की बजाय हवाई मार्ग अपनाया। काठमांडू से दिल्ली और फिर रेल द्वारा नागपुर तक का सफर तय किया.

ठेकेदार आक्रामक, पुलिस से नोकझोंक



नागपुर : 1890 करोड़ रुपए के बिल का भुगतान पेंडिंग होने से आहत ठेकेदारों ने रवि भवन में पीडब्ल्यूडी मंत्री के लिए आरक्षित कॉटेज क्रमांक 6 के समक्ष आत्महत्या करने वाले ठेकेदारों को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान श्रद्धांजलि का बोर्ड हटाने की अपील पर ठेकेदारों की पुलिस से नोकझोंक भी हो गई.

पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवेंद्र राजे भोंसले बुधवार से नागपुर विभाग के दौरे पर हैं. उन्हें रवि भवन में आरक्षित कॉटेज क्रमांक 6 आरक्षित है. आज दोपहर 2 बजे नागपुर कां्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले ठेकेदारों ने यहां मृत ठेकेदारों को श्रद्धांजलि देने की सभा आयोजित की. उनका कहना है कि पेंडिंग बिल का भुगतान नहीं होने से नागपुर के ठेकेदार मुझा वर्मा, सांगली के हर्षल पाटिल और नांदेड़ के गजाभाऊ देवकाते ने आत्महत्या की है.

पीडब्ल्यूडी मंत्री के कॉटेज में श्रद्धांजलि सभा

एकोना कोयला खदान में हो रहे विस्फोटों को रोकें: धानोरकर



चंद्रपुर: वरोरा शहर के समीपस्थ वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की एकोना कोयला खदान में प्रतिदिन दोपहर 3 से 4 बजे के बीच होने वाले भीषण विस्फोटों से वरोरा शहर के 3 से 4 वार्डों के नागरिकों और व्यापारियों के बीच भय का माहौल पैदा कर दिया है. विस्फोटों के कंपन से स्थानीय नागरिकों के घरों की दीवारों में बड़ी दरारें आना, प्लास्टर का गिरना और खिड़कियों को नुकसान पहुंचने जैसी गंभीर समस्याएं लगातार हो रही हैं. भविष्य में बड़े हादसों और जान-माल के नुकसान का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए प्रभावित नागरिकों, स्थानीय जन प्रतिनिधियों और क्षेत्र के पदाधिकारियों ने सांसद प्रतिभा धानोरकर से मुलाकात करके समस्या की गंभीरता से अवगत

कराया. समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए मंगलवार को वरोरा के उप-मंडल अधिकारी के कार्यालय में वेकोलि के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई.

इस दौरान सांसद प्रतिभा धानोरकर को आक्रामक रुख की देखते हुए वेकोलि प्रशासन ने आश्वासन दिया कि अगले 15 दिनों में वेकोलि के अधिकारी विशेष मापदंड स्थापित करेंगे ताकि विस्फोटों से होने वाले कंपन और तीव्रता का भौतिक निरीक्षण किया जा सके और भविष्य में नागरिकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा. सांसद प्रतिभा धानोरकर ने प्रभावित घरों का भौतिक निरीक्षण करने और जांच कराने के निर्देश दिए.

ग्रामीण अस्पताल १ अक्तूबर तक शुरू होने की संभावना

चंद्रपुर : घुघुस स्थित ३० बेड वाले नवनिर्मित ग्रामीण अस्पताल के शुरू होने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है. जिलाधिकारी वसुमना पंत के दौरे तथा संबंधित विभागों से तीखे सवाल पूछे जाने और फाइनल डेड लाइन मांगे जाने के बाद संबंधित विभाग की हलचलें तेज हो गई हैं.

हालांकि संबंधित विभागों द्वारा पहले १ अक्तूबर के डेड लाइन दी गई. लेकिन जिलाधिकारी वसुमना पंत ने पूछा कि सही सही बताएं क्या उस दिन तक शुरू हो जाएगा तो संबंधित विभागों ने नवंबर माह की पहले सप्ताह का समय दिया है. जिससे हर हाल में घुघुस ग्रामीण अस्पताल शुरू होने की संभावना बढ़ गई है.

जिलाधिकारी पंत ने रक्षा बंधन के दिन घुघुस ग्रामीण अस्पताल का निरीक्षण किया. उन्होंने १० दिनों में आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश देते हुए कहा १ अक्तूबर तक सेवाएं शुरू की जानी चाहिए. सभी संबंधित विभागों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए. जिससे अब घुघुस ग्रामीण अस्पताल जन सेवा में समर्पित होने की उम्मीद बढ़ गई है.

यवतमाल में आदिवासी छात्रों का आंदोलन जारी

यवतमाल : आदिवासी छात्रों का यवतमाल में जिला परिषद के सामने विभिन्न मांगों को लेकर गत दस दिनों से आंदोलन जारी है. आंदोलन वापस लेने को लेकर प्रशासन ने उनसे चर्चा की, हालांकि वे अपनी मांगों पर अडिग हैं. शनिवार को जिलाधिकारी विकास मीणा की अध्यक्षता में समिति के साथ अनशनकर्ताओं की बैठक हुई. हालांकि इस बैठक में मांगों को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाया. इससे यह आंदोलन १ सितंबर तक जारी रहने की बात छात्र प्रतिनिधियों ने स्पष्ट की. इस बीच मंत्री अशोक उईके के घर का विधार्थियों द्वारा घेराव की आशंका के चलते पुलिस प्रशासन ने शनिवार को शहर में उनके राणाप्रताप नगर स्थित आवास की सुरक्षा बढ़ा दी. शनिवार को तड़के से ही राणाप्रताप नगर की ओर आने वाले सभी मार्गों पर पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया.

आदिवासी छात्रों का यह ‘लांग मार्च’ पिछले दो दिनों से यवतमाल की ओर बढ़ रहा था. शुक्रवार की रात छात्र बाभुलगांव स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में थे. शनिवार की आधी रात को आदिवासी विकास मंत्री सीधे

आंदोलन स्थल पर पहुंचे. छात्रों की लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई. मांगों को मानने की शर्त पर और मुख्यमंत्री के साथ बैठक के आश्वासन के बाद आंदोलनकारी शांत हुए.

नागपुर में 8 डिग्री गिरा पारा

16.9 मिमी बारिश दर्ज

नागपुर : नागपुर में शनिवार

मौसम का मिजाज बदला और तड़के ५ बजे से ही शहर के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश हुई. रुक-रुककर बारिश का दौरा देर रात तक जारी रहा. हल्की से मध्यम रफ्तार में लगातार बारिश होने से दिन का तापमान चौबीस घंटे में ८ डिग्री गिरकर २५.६ डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा. जबकि रात का तापमान २२.४ डिग्री दर्ज किया गया. ऐसे में दिन और रात के तापमान में ३.२ डिग्री का अंतर दर्ज किया गया. अचानक से तापमान में गिरावट की वजह से वातावरण की गर्मी पूरी तरह खत्म हो गई और मौसम खुशनुमा हो गया.

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नागपुर में सुबह ८.३० बजे तक ६.९ और सुबह ८.३० से लेकर शाम ५.३० बजे तक १० मिमी बारिश दर्ज की गई. नागपुर में सुबह और शाम के समय आद्रता ९६ फीसदी दर्ज की गई. इसके अलावा गोंदिया में सुबह ८.३० बजे तक २४.२ मिमी व शाम ५.३० बजे तक ७ मिमी

बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा ब्रह्मपुरी में शाम ५.३० बजे तक १२ मिमी, वर्धा में १७, यवतमाल में १३, अमरावती व चंद्रपुर में २-२ मिमी बारिश दर्ज की गई. विदर्भ के अधिकांश जिलों में शनिवार को तीन डिग्री से लेकर ८ डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई. विदर्भ के अधिकांश जिलों में २९ अगस्त के समान ही ३० अगस्त को कई जिलों में अच्छी बारिश के आसार जताए गए हैं. इसके अलावा ३ और ४ सितंबर को भी बारिश के आसार बन रहे हैं.

कम दबाव के क्षेत्र का असर

बंगाल की खाड़ी में तैयार हुए कम दबाव के क्षेत्र की वजह से विदर्भ का मौसम बदला है. आगामी दो दिनों में पश्चिम-उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा. वर्तमान में मानसूनी ट्रफ रेखा अमृतसर, नजीबाबाद, बरेली, गोरखपुर, रांची होते हुए पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है. ऐसे में फिलहाल मध्यभारत की मानसूनी गतिविधि पूरी तरह बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से तैयार हुई है.

अजब-गजब ।एमबीसीबी की जांच रिपोर्ट में सच हुआ उजागर

महामाया : अवैध रूप से भूजल का उपयोग ! : सीजीडब्ल्यूए की एनओसी के बिना दिया ओपनिंग आदेश

संवाददाता । चंद्रपुर

चंद्रपुर तहसील के बेलसनी स्थित महामाया इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की ‘माया’ की चर्चा चंद्रपुर से मुंबई तक शुरू हो गई है. महामाया के ‘मायाजाल’ में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चंद्रपुर स्थित प्रादेशिक अधिकारी कार्यालय से लेकर मुंबई मुख्यालय तक उलझ कर रह गया है. ऐसे में बेलसनी स्थित महामाया इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की कोयला वॉशरी को केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण की ‘एनओसी’ के बिना ही एमपीसीबी ने ‘कंसेट टू ऑपरेट’ अर्थात ओपनिंग आदेश दे दिया है. जिससे इस मामले में राज्य के पर्यावरण विभाग की मंत्री पंकजा मुंडे से लेकर



महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के मुख्यालय में बैठने वाले अध्यक्ष विभाग के सिद्धेश कदम तथा विभाग के सदस्य सचिव आईएसए अधिकारी राहुल रेखावार की

कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लग गया है. विदित रहे कि एमपीसीबी चंद्रपुर स्थित विभाग के प्रादेशिक अधिकारी तानाजी यादव ने लिखित आदेश में पहले

सक्षम अधिकारी का नाम आदेश में नहीं

इसके बावजूद 31 जुलाई 2026 के आदेश के बिंदु क्रमांक 9 में प्रादेशिक अधिकारी तानाजी यादव ने कहा है कि, ‘आपको एमबीसीबी मुख्यालय के सक्षम अधिकारी के आदेश से कोयला वॉशरी शुरू करने की अनुमति दी जा रही है लेकिन आपको घरेलू जल के उपयोग के लिए सीजीडब्ल्यूए से प्राप्त एनओसी का नवीनीकरण करना होगा.’ आदेश में सक्षम अधिकारी के नाम का उल्लेख नहीं होने से यह स्पष्ट नहीं है कि वह एमपीसीबी का वह सक्षम अधिकारी कौन है?, जिसके आदेश पर प्रादेशिक अधिकारी तानाजी यादव संबंधित कंपनी द्वारा जरूरी कामजात पूर्ण किए ही आनन फानन में ‘ओपनिंग’ आदेश दे रहे हैं.

ही स्पष्ट कर दिया है कि वह मुख्यालय के आदेश पर ‘ओपनिंग’ आदेश दे रहे हैं.

चंद्रपुर स्थित उप-क्षेत्रीय कार्यालय के बोर्ड अधिकारियों ने 19 जून 2026 को महामाया इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड उद्योग का दौरा किया था. जिससे संदर्भ संख्या 10.6 के तहत जारी निर्देशों के

अनुपालन की स्थिति की जांच करने पर कई अनियमितताएं पाई गईं. नोटिस में कहा गया है कि भूजल निकालने के लिए केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) की एनओसी प्राप्त किए बिना बोरवेल और टैंकर के पानी का उपयोग किया जा रहा है.

निवेश परिषद से रोजगार बढ़ने की संभावना

उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत ने सरकारी नीति का किया खुलासा



संवाददाता । वर्धा
वर्धा में उद्योगों की क्षमता और स्थानीय उद्यमियों का उत्साह सराहनीय है. जिले के औद्योगिक विकास के लिए

सरकार हरसंभव सहयोग करेगी, यह आश्वासन उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत ने दिया. जिलानिवेश परिषद में कुल 3 हजार 11 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन

वर्धा में उद्योग लाने का प्रयास करेंगे : पालकमंत्री

जिले में निवेश बढ़ाकर स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. जिले में आयोजित निवेश परिषद से वर्धा के उद्योगों को नई दिशा मिलेगी, ऐसा विश्वास पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने व्यक्त किया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में राज्य में अनेक उद्योग और निवेश परियोजनाएं आई हैं. इस बढ़ी हुई कनेक्टिविटी का लाभ स्थानीय उद्यमियों, किसानों और उद्योगों को दिलाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के माध्यम से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है, ऐसा डॉ. भोयर ने स्पष्ट किया.

(एमओयू) किए गए हैं.

इस निवेश से जिले में रोजगार बढ़ाने में गति मिलेगी, ऐसा विश्वास उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत ने व्यक्त किया. जिला उद्योग केंद्र की ओर से आशीर्वाद सेलिब्रेशन

हॉल में जिला स्तरीय निवेश परिषद का आयोजन किया गया था. इस अवसर पर वे संबोधित कर रहे थे. कार्यक्रम में पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर, जिलाधिकारी वान्मथी सी, जिला पुलिस

अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा की परिवीक्षाधीन अधिकारी शोभिता पाठक, एमआईडीसी संगठन के अध्यक्ष प्रवीण हिवरे, उद्योग एवं सेवा सहआयुक्त शिवकुमार मुद्दमवार, लघु उद्योग भारती के महामंत्री हरीश हांडे, जिला उद्योग केंद्र के उद्योग एवं सेवा सहायक आयुक्त सुनील हजारे सहित अन्य उपस्थित थे. उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास जिले के उद्योगों, स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने तथा पर्यावरणपूरक उपक्रमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. विशेष रूप से प्लास्टिक के विकल्प के रूप में कांच की बोतलों में उत्पादों की पैकेजिंग करने का वर्धा का प्रयोग पूरे राज्य के लिए आदर्श है. पर्यावरणपूरक तरीके से उत्पादन हो चाहिए.

ग्रामसभाओं का अधिकार मजबूत करेंगे



संवाददाता । गड़चिरोली

‘मावा नाटे, मावा राज’ यानि ‘हमारा गांव, हमारा राज’ और ‘जल, जंगल, जमीन हमारा है’ के विचार को मजबूत करने के लिए गड़चिरोली जिले की करीब 1,400

ग्रामसभाओं को सशक्त बनाने का अभियान चलाया जाएगा. इसके लिये ग्रामसभा लेखा ‘मैंदा’ के प्रमुख समाजसेवी देवाजी तोफा ने पहल की है. इस संदर्भ में शुक्रवार को ग्रामसभा कार्यालय

ग्रामसभा मंत्रालय’ इस विचार के साथ ग्रामसभाओं को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाएगा.

ग्रामसभा यात्रा गड़चिरोली

जिले की सभी ग्रामसभाओं को उन अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देने के लिए कोरची से सिरोंचा तक विराट ग्रामसभा यात्रा निकाली जाएगी.

इस यात्रा के माध्यम से जिले के विभिन्न तहसीलों की ग्रामसभाओं से स्थानीय समस्याओं की जानकारी एकर की जाएगी. इसके लिए ग्रामसभाओं की समस्याओं को लेकर एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की जाएगी. अभियान के समापन पर जिले भर की ग्रामसभाओं से प्राप्त समस्याओं और मांगों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

कोरची से सिरोंचा तक ग्रामसभा यात्रा, मावा नाटे, मावा राज

पुलिस की कार्रवाई, २ आरोपी गिरफ्तार

४ नवंबर को जारी की जाएगी अंतिम सूची



संवाददाता । गड़चिरोली

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम में संशोधन किया है. इसके अनुसार 31 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूचियां प्रकाशित की जाएंगी, जबकि 4 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूचियां प्रकाशित की जाएंगी. भारत निर्वाचन आयोग ने 14 मई 2026 को जारी पत्र के माध्यम से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया था. इसके बाद आयोग द्वारा 19 अगस्त 2026 को जारी पत्र के अनुसार कार्यक्रम में संशोधन कर नई समय-सारिणी

निर्धारित की है. संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदान केंद्रों का युक्तिकरण एवं पुनर्गठन 24 अगस्त 2026 को किया जाएगा. इसके बाद 31 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूचियां प्रकाशित होने के बाद नागरिक अपने नाम और अन्य विवरणों की जांच कर सकेंगे तथा आवश्यकता होने पर दावे एवं आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे.

30 सितंबर तक दर्ज करे आपत्ति प्रारूप मतदाता सूची पर दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने के लिए 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है. इस अवधि में प्राप्त

31 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन

दावों और आपत्तियों पर निर्वाचन विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

दावों एवं आपत्तियों के संबंध में नोटिस जारी करने तथा प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर 2026 तक पूरी की जाएगी. सभी दावों एवं आपत्तियों का निपटारा होने के बाद मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा. विशेष गहन पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 4 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से अपील की है कि, प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद वे अपना नाम एवं अन्य विवरण अवश्य जांच लें. किसी प्रकार की त्रुटि या आपत्ति होने पर निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति दाखिल करें. मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम उपजिला निर्वाचन अधिकारी जाधव ने जारी किया है.

लांग मार्च से शासन जागा, मंत्री उईके ने तत्काल बुलाई बैठक



संवाददाता । बाभुलगांव

अमरावती संभाग के आदिवासी विद्यार्थियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर निकाला गया लांग मार्च आखिरकार शासन को जगाने में सफल रहा. 325 आदिवासी विद्यार्थियों की मांगों को लेकर 28 अगस्त को अमरावती से शुरू हुआ लांग मार्च यवतमाल होते हुए बाभुलगांव पहुंचा. यहां कृषि उपज मंडी परिसर में विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में धरना देकर शासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई. आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके रात करीब 11.30 बजे आंदोलन स्थल पर पहुंचे. उन्होंने विद्यार्थियों से चर्चा कर उनकी 19 मांगों को सुना. प्रत्येक मांग पर लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद रात करीब ढाई बजे चर्चा के माध्यम से समाधान निकाला गया.

इसके बाद सुबह 9 बजे

विद्यार्थियों को बाभुलगांव से आगे के सफर के लिए रवाना किया गया. ‘कंडिशनल वैलिडिटी’ समेत अन्य जटिल शर्तों के विरोध में विद्यार्थियों ने आंदोलन किया था. सरकार की ओर से 5 अगस्त 2026 और 14 अगस्त 2026 को जारी दोनों शासन निर्णय रद्द करने की जानकारी दी गई. साथ ही 11 नवंबर 2011 के शासन निर्णय में आवश्यक बदलाव कर एक महिने के भीतर नया जीआर जारी करने का आश्वासन दिया गया. इसमें आयुसीमा पूरी तरह समाप्त करने की बात कही गई है. पुणे, मुंबई, नागपुर और संभाजीनगर के विश्वविद्यालय परिसरों में आदिवासी विद्यार्थियों के लिए नए छात्रावास बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन भी दिया गया है. आदिवासी विद्यार्थियों की शेष मांगों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए 1 सितंबर को मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है.

साखरी-पोवणी मार्ग पर ट्रकों की अवैध पार्किंग

राजुरा : साखरी से पोवणी मार्ग पर पिछले कई दिनों से सड़क के दोनों ओर करीब दो किलोमीटर तक ट्रकों की अवैध पार्किंग की जा रही है. इसके चलते इस मार्ग से आने-जाने वाले नागरिकों, किसानों और स्कूली विद्यार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस गंभीर समस्या की ओर वेकोलिव एवं पुलिस प्रशासन द्वारा कथित रूप से अनदेखी किए जाने से नागरिकों में नाराजगी है. नागरिकों का सवाल है कि क्या किसी जनहानि इस मार्ग से प्रतिदिन विद्यार्थी राजुरा और साखरी स्थित स्कूलों में जाते हैं. सड़क पर ही ट्रकों की पार्किंग होने के कारण विद्यार्थियों को रोजाना यातायात संबंधी परेशानियों का सामना करते हुए स्कूल जाना पड़ रहा है. साखरी गांव के मुख्य प्रवेश द्वार के आसपास तथा स्कूल के प्रवेश द्वार के सामने भी वाहनों की पार्किंग की जा रही है, जिससे यहां कभी भी गंभीर दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है.

कामबंद आंदोलन की दी गई चेतावनी

संवाददाता । वर्धा

राज्य के द्वितीयक न्यायालयों में कार्यरत करीब 34 हजार न्यायालयीन कर्मचारियों के समान वेतन का प्रस्ताव 31 जनवरी 2025 से शासन स्तर पर लंबित है. अब तक मंजूरी नहीं मिलने से कर्मचारियों में नाराजगी है. लंबित प्रस्ताव पर तत्काल निर्णय लेकर समान वेतन लागू करने की मांग को लेकर राज्यभर के न्यायालयीन कर्मचारियों ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है. बैठक में हुई चर्च इस संबंध में मुंबई में चारों महासंघों के पदाधिकारियों के साथ महाराष्ट्र के सभी जिलों के जिला अध्यक्षों एवं अन्य पदाधिकारियों की



बैठक हुई. बैठक में लंबित वेतनवृद्धि प्रस्ताव तथा शासन स्तर पर हो रही देरी पर चर्चा की गई. शासन द्वारा तत्काल निर्णय नहीं लिए जाने की स्थिति में चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया. आंदोलन के पहले चरण में 16 सितंबर को काली पट्टी बांधकर विरोध किया जाएगा. इसके बाद 16 और 17 अक्टूबर को दो दिनों तक काली पट्टी

बांधकर न्यायालयीन कामकाज किया जाएगा. इसके बावजूद मांगों का समाधान नहीं होने पर 5 नवंबर 2026 को वसुबारस के दिन सामूहिक अवकाश आंदोलन किया जाएगा. इसके बाद भी शासन ने मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो 6 और 7 नवंबर को न्यायालयीन कर्मचारी अन्नत्याग आंदोलन करेंगे. 17 नवंबर से

अनिश्चितकालीन हड़ताल मांगें मंजूर नहीं होने पर 17 नवंबर 2026 से राज्य के सभी द्वितीयक न्यायालयों के न्यायिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे. वर्धा जिले के न्यायालयीन कर्मचारी भी इस राज्यव्यापी आंदोलन में सक्रिय रूप से सहभागी होंगे. आंदोलन के माध्यम से शासन से 31 जनवरी 2025 से लंबित समान वेतन के प्रस्ताव पर तत्काल निर्णय लेकर कर्मचारियों को न्याय देने की मांग की गई है. वर्धा जिले में चारों जिला न्यायालयीन कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष सतीश तांबुसकर, संदीप माडे, कमलाकर चापके और गोपाल साहू ने आंदोलन में शामिल होने की चेतावनी दी है. उन्होंने शासन से कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है.

झमाझम बारिश से किसानों को राहत



वर्धा : पिछले कई दिनों से बारिश के इंतजार में बैठे किसानों को शुक्रवार रात से शुरू हुई बारिश ने बड़ी राहत दी है. शनिवार को भी जिले के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहा. बारिश के अभाव में मुरझाने लगी खरीफ फसलों को इससे संजीवनी मिली है. जिले में 4 लाख 18 हजार 783.51 हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसलों के लिए यह बारिश महत्वपूर्ण मानी जा रही है. बारिश की वापसी से विशेषकर सूखाग्रस्त किसानों के चेहरे खिल उठें हैं.

फसलों पर पड़ रहा था प्रभाव जिले में अगस्त महिने के दौरान बारिश ने लंबा विराम लिया था. कई दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने के बावजूद पर्याप्त बारिश नहीं हुई. हल्की फुहारों के कारण फसलों की वृद्धि प्रभावित होने लगी थी. सोयाबीन, कपास, तुअर और मक्का सहित अन्य फसलों पर रोगों का प्रकोप भी

दिखाई देने लगा था. जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा थी, उन्होंने फसलों को बचाने के लिए ड्रिप और प्रिकलर से पानी देना शुरू कर दिया था. 21 और 22 अगस्त को हुई बारिश के बाद फसलें बारिश गायब हो गई थी. इससे किसानों की चिंता बढ़ गई थी. शुक्रवार रात से शुरू हुई अच्छी बारिश ने किसानों को राहत दी है. बंधी आस आगामी दिनों में भी पर्याप्त बारिश होने पर फसलों की स्थिति और बेहतर होने की उम्मीद है. इस वर्ष जिले में 4 लाख 6 हजार 554.85 हेक्टेयर खरीफ फसलों की बुआई का लक्ष्य था. मानसून के करीब 10 से 12 दिन देरी से आने के बावजूद किसानों ने लक्ष्य से अधिक क्षेत्र में बुआई पूरी की. कुल 4 लाख 18 हजार 783.51 हेक्टेयर यानी लक्ष्य के 103 प्रतिशत क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई हुई है. कपास, सोयाबीन, तुअर, मूंग, उड़द और मक्का प्रमुख फसलें हैं.

आवारा मवेशियों से देवली बेहाल

15 साल से कांजी हाउस का इंतजार, नगरपालिका की अनदेखी

संवाददाता । देवली

करीब 25 हजार की आबादी वाले देवली शहर में पिछले 15 वर्षों से मवेशियों को रखने के लिए कांजी हाउस की व्यवस्था नहीं होने के कारण आवारा पशुओं की समस्या गंभीर होती जा रही है. शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में गाय, बछड़े और सांड़ आसपास घूमते और डेरा जमाए दिखाई देते हैं. नगरपालिका प्रशासन द्वारा

लंबे समय से इस समस्या की अनदेखी किए जाने से नागरिकों में नाराजगी बढ़ रही है. जानकारी के अनुसार, शहर में करीब 50 आवारा मवेशियों का झुंड घूमता रहता है. दिन के समय ये मवेशी शहर की प्रमुख सड़कों और चौक-चौराहों पर बैठे रहते हैं. वहीं रात के समय आसपास के खेतों में पहुंचकर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं.

इससे पहले ही विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. देवली शहर के दहेगांव चौफुली, नांदोरा चौफुली, सोनेगांव चौफुली सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर आवारा मवेशियों ने अपना डेरा बना लिया है. कई बार इन मवेशियों के कारण दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं.

नागरिकों का कहना है कि

यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में कोई बड़ा और गंभीर हादसा हो सकता है. नगरपालिका प्रशासन से आवारा मवेशियों का तत्काल बंदोबस्त करने की मांग की है. नागरिकों के अनुसार शहर में स्थायी रूप से कांजी हाउस की व्यवस्था की जानी चाहिए और पकड़े गए आवारा मवेशियों को वहां रखा जाना चाहिए.

विवादों में कमी आयी

शराबबंदी के कारण गांव के विवाद कम हुए हैं. बच्चे शिक्षा में मन लगा रहे हैं. शराबमुक्ति के कारण गांव विकास की ओर अग्रसर हैं. गांव के संपूर्ण परिवार मिलकर यह विजयोस्तव श्रमदान के माध्यम से संपन्न कराया. इस समय पुलिस पटेल अमर हलामी, गांव पटेल माणिक हलामी, मन्साराम उईके, धनराम तुलावी, पांडुरंग हलामी, रामजी हलामी, राकेश नैताम, लक्ष्मण बोगा, लक्ष्मण हलामी, गांव संगठना अध्यक्ष लता तुलावी, स्वास्थ्य केंद्र मोडेभट्टी के उंदीरवाडे समेत ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे. कार्यक्रम का नियोजन मुक्तिपथ तहसील संगठक राहुल महाकुलकर, तहसील प्रेरक बुधा पोरटे, मुक्तिपथ कार्यकर्ता शितल गुरुनूले ने किया.

उपक्रम शांतिमय रूप से संपन्न हो रहे हैं.

मोडेभट्टी में 30 वर्षों से शराबबंदी का नियम

संवाददाता । गड़चिरोली

गड़चिरोली जिले में वर्ष 1992 में शराबबंदी लागू हुई है. लेकिन अवैध शराब बिक्री की समस्या कायम है. लेकिन धानोरा तहसील के मोडेभट्टी गांव में वर्ष 1995 से अवैध शराब पर भी पाबंदी लगाते हुए यह शराबबंदी कायम रखते हुए इतिहास रचा है. मोडेभट्टी गांव में विगत 30 वर्षों से शराबबंदी कायम है. जिससे हाल ही में मुक्तिपथ के मार्गदर्शन में विभिन्न उपक्रम लेकर शराबमुक्ति का विजयोत्सव गांव में मनाया गया. कार्यक्रम के



खुशहाल जीवन, शिक्षा के स्तर में आया बड़ा सुधार



दौरान शराबबंदी का महत्व बताया गया.

जीवन हुआ खुशहाल दुर्गम क्षेत्र में बसे मोडेभट्टी गांव में वर्ष 1995 से शराबबंदी है. इस गांव में नशे का प्रमाण कम है. ग्रामीण खुशहाल रूप से जीवनयापन कर रहे हैं. पूर्व से कायम शराबबंदी को खतरा न पहुंचे इसलिए मुक्तिपथ व शक्तिपथ संगठना, गांव के प्रतिष्ठित

नागरिक सतर्कता बरत रहे हैं. इस सफलतम कार्य की जानकारी अन्यों को मिले, इसके लिए गांव में शराबबंदी का विजयस्तंभ निर्माण करने का निर्णय लिया. जिसके तहत ग्रामीणों ने गांव में मुक्तिपथ के मार्गदर्शन में गांव में शराबबंदी का विजयोत्सव मनाया. इस विजयोत्सव में संपूर्ण ग्रामीण शामिल हुए थे. इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि, गांव में शराबबंदी है. तब से विभिन्न

ग्रामसभाएं सुरक्षित हों, वरना बंद की जाएं!

अधिकारी-कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी यूनियन ने विधायक विजय रहांगडाले को सौंपा ज्ञापन

संवाददाता / तिरोड़ा

बदलते डिजिटल युग में ग्रामसभा की कार्यप्रणाली पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ग्रामसभाओं में अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ मारपीट, धमकी, गाली-गलौज और दबाव की घटनाओं को रोकने के लिए ग्रामसभा प्रणाली को या तो समाप्त किया जाए अथवा उसके संचालन के लिए कड़े कानूनी नियम लागू किए जाएं, ऐसी मांग महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत अधिकारी यूनियन के पदाधिकारियों ने तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय रहांगडाले से ज्ञापन के माध्यम से की है। ग्रामसभा ग्रामीण लोकतंत्र में



नागरिकों की भागीदारी का महत्वपूर्ण मंच मानी जाती है। हालांकि, कुछ स्थानों पर ग्रामसभाओं के दौरान अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधियों पर दबाव

बनाने, गाली-गलौज, धक्कामुक्की तथा मारपीट जैसी घटनाएं बढ़ने का दावा यूनियन ने किया है। ज्ञापन में जलगांव जिले में हाल ही में हुई एक गंभीर

‘ग्रामसभा संहिता’ लागू करने की मांग

यूनियन ने मांग की है कि ग्रामसभा समाप्त करने का निर्णय होने तक उसके सुचारु एवं सुरक्षित संचालन के लिए स्वतंत्र ‘ग्रामसभा संहिता’ लागू की जाए। इसमें ग्रामसभा के दौरान अधिकारी-कर्मचारियों तथा नागरिकों की सुरक्षा, अनुशासन एवं कानून-व्यवस्था से संबंधित स्पष्ट नियम निर्धारित किए जाएं।

घटना का हवाला देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था से संबंधित स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई है। डिजिटल युग में ग्रामसभा की कार्यप्रणाली पर पुनर्विचार की मांग यूनियन का कहना है कि वर्तमान समय में सरकारी योजनाओं, शासनादेशों और विभिन्न सरकारी गतिविधियों की जानकारी सोशल

मीडिया, ऑनलाइन पोर्टल तथा अन्य डिजिटल माध्यमों से नागरिकों तक आसानी से पहुंच रही है। लाभार्थियों के चयन के लिए भी ऑनलाइन एवं पारदर्शी प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं। ऐसे में ग्रामसभा में होने वाली कुछ मंजूरी प्रक्रियाएं केवल औपचारिकता बनकर रह गई हैं। ग्रामसभा का मूल उद्देश्य

पुलिस बंदोबस्त के बिना ग्रामसभा आयोजित न हो

ग्रामसभा के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए प्रत्येक ग्रामसभा को अनिवार्य एवं निःशुल्क पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। पुलिस बंदोबस्त के बिना ग्रामसभा आयोजित न की जाए, ऐसी स्पष्ट मांग भी ज्ञापन में की गई है।

जनभागीदारी सुनिश्चित करना है, लेकिन कुछ स्थानों पर व्यक्तिगत विवाद, राजनीतिक गुटबाजी तथा आरोप-प्रत्यारोप के कारण विकास के मुद्दों के

बजाय विवाद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलने की बात यूनियन ने कही है। यूनियन ने विधायक विजय रहांगडाले से अनुरोध किया कि इस गंभीर विषय को आगामी विधानसभा अधिवेशन में प्रभावी ढंग से उठाकर आवश्यक कानून एवं नियमों में संशोधन के लिए पहल की जाए। संघटना ने स्पष्ट किया कि ग्रामसभा लोकतंत्र की महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन अधिकारी-कर्मचारियों की सुरक्षा, नागरिकों की भागीदारी और ग्रामविकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ग्रामसभा की कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार करना अब समय की आवश्यकता है।

सेंट्रल डिजिटल फसल सर्वे से किसान त्रस्त

नवेगांव बांध में तकनीकी गड़बड़ी और मनमानी से फसल पंजीयन हो रहा प्रभावित

संवाददाता / नवेगांव बांध

खरीफ सीजन में फसलों के पंजीयन के लिए इस वर्ष लागू किए गए ‘सेंट्रल डिजिटल क्राॅप सर्वे’ से किसान परेशान हैं। प्रशासन की जटिल प्रक्रिया और समन्वय के अभाव के कारण खेतों में मेहनत करने वाले किसानों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ रही है। पहले किसान ‘ई-पीक पाहनी’ एप के माध्यम से अपने खेत में बोई गई फसल का पंजीयन

स्वयं आसानी से कर लेते थे। लेकिन इस वर्ष राजस्व विभाग ने यह जिम्मेदारी पुलिस पाटिल सहित अन्य कर्मचारियों को सर्वेक्षण सहायक के रूप में सौंपी है। किसानों का आरोप है कि कई स्थानों पर सर्वेक्षण सहायकों और किसानों के बीच उचित समन्वय नहीं हो पा रहा है। किसानों का कहना है कि जब सर्वेक्षण सहायक खेत में पहुंचते हैं, तब कई बार किसान वहां मौजूद नहीं रहते। वहीं, किसान संपर्क करते हैं तो



संबंधित सहायक अन्य काम में व्यस्त होने का हवाला देकर टालमटोल करते हैं। कुछ स्थानों पर फसल

पंजीयन किया है या नहीं, इसकी जानकारी जांचने की स्पष्ट सुविधा एप में उपलब्ध नहीं होने से पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि फसल का पंजीयन समय पर और सही तरीके से नहीं हुआ तो किसानों को फसल बीमा, प्राकृतिक आपदा सहायता, सरकारी धान खरीदी केंद्र और बोनस जैसे महत्वपूर्ण लाभों से वंचित होना पड़ सकता है। किसानों ने चेतावनी दी है कि ऐसी स्थिति के लिए संबंधित पटवारी और राजस्व विभाग को जिम्मेदार माना जाएगा।

40 फुट की सड़क हुई 15 फुट की; यातायात की जाम

पुलिस विभाग के अभियान के बाद स्थिति फिर ‘जैसे थे’

संवाददाता / आमगांव

कुछ दिनों पहले आमगांव पुलिस विभाग ने व्यापारियों व दुकानदारों की बैठक लेकर वाहनों को सफेद पट्टी के अंदर खड़ा करने के निर्देश दिए थे। इस जनजागरूकता अभियान का प्रभाव दो दिन रहा और सड़कें खुली दिखाई देने लगीं। हालांकि, पुलिस का अभियान ठंडा पड़ते ही स्थिति फिर पूर्ववत हो गई है। वर्तमान में दोपहिया, चारपहिया, स्कूल बस, इलेक्ट्रिक ऑटो और यात्री वाहनों को सीधे सड़क के बीचोंबीच या किनारे जैसे-तैसे खड़ा किया जा रहा है।

सड़क के दोनों ओर खड़े किए जाने वाले वाहनों के कारण शहर की 40 फुट की सड़कें क्षणभर में 15 फुट की हो जाने का चित्र दिखाई दे रहा है। शहर के अंबेडकर चौक से बसस्थानक मार्ग पर स्टेट बैंक के सामने रोजाना वाहनों की लंबी-



लंबी कतारें लगती हैं, छोटे व्यापारी, चाय-नाश्ते की दुकानें व ग्राहकों की अव्यवस्थित पार्किंग के कारण ईगमुळे सड़क संकरी हो जाती है। अंबेडकर चौक से गांधी चौक मार्ग पर प्रमुख बाजार, रेस्टोरेंट्स और दुकानों के कारण यहां बड़ी भीड़ रहती है। सड़क के दोनों ओर वाहन खड़े रहने से आमने-सामने से आने वाले वाहनों के लिए जगह नहीं बचती, जबकि पैदल यात्रियों को जान हथेली पर रखकर चलना पड़ता है। केवल एक-दो दिनों के अभियान से यह

समस्या हल नहीं होगी। सड़क पर दुकानों का सामान रखना, ऑटोचालकों द्वारा सड़क के बीचोंबीच यात्रियों को चढ़ाना-उतारना और गलत दिशा में वाहन चलाने पर भी कड़े प्रतिबंध होने चाहिए, शहर में निश्चित ‘पार्किंग’ व ‘नो-पार्किंग’ जोन घोषित कर नियम तोड़ने वालों पर नियमित दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में होने वाली बड़ी दुर्घटनाओं को टाला जा सके, ऐसी आमगांव मांग शहरवासियों द्वारा की जा रही है।

जिले में मेघ फिर मेहरबान, कहीं रिमझिम, कहीं मध्यम बारिश से मौसम खुशनुमा

संवाददाता / गोंदिया

गोंदिया जिले में 28 अगस्त की रात से फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। 29 अगस्त को भी गोंदिया शहर सहित जिले के लगभग सभी तहसीलों में सुबह से ही कहीं-कहीं तो कहीं मध्यम बारिश होने की जानकारी मिली है। लगातार हो रही बारिश का असर सामान्य जनजीवन पर दिखाई दे रहा है। सड़कों पर चौपहिया एवं ईक्का-दुक्का दोपहिया वाहन ही दिखाई पड़ रहे हैं। बाजार क्षेत्र में भी सड़कों पर अपेक्षाकृत कम यातायात दिखाई पड़ रहा है। लगातार बारिश होने से वातावरण ठंडा बना हुआ है। लेकिन किसानों और कृषि विभाग ने इस बारिश को खेती के लिए फायदेमंद बताया है। जिलाधिकारी कार्यालय के नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अर्थात् 29 अगस्त को दोपहर 2 बजे तक जिले में कुल मिलाकर 11.2 मिमी औसतन बारिश रिकार्ड की गई है। इस अवधि में सर्वाधिक 28.1 मिमी



पुजारीटोला का बढ़ा जलस्तर

बारिश के चलते सालेकसा तहसील में स्थित पुजारीटोला जलाशय के जलस्तर में हो रही वृद्धि को देखते हुए जलस्तर को नियंत्रित बनाए रखने के लिए 29 अगस्त को सुबह 10 बजे पुजारीटोला जलाशय के 5 गेट 0.30 मीटर तक खोले गए हैं, जिससे 3 हजार 974 क्यूसेक पानी नदीपात्र में छोड़ा जा रहा है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से नदीपात्र की ओर न जाने और सतर्कता बरतने को कहा गया है। किसी भी नागरिक को कोई परेशानी होने पर फोन क्र. 07182-230196 अथवा मोबाइल क्र. 9404991599 पर संपर्क करने का आह्वान किया गया है।

बारिश गोरेगांव तहसील में दर्ज की गई है।

इसके अलावा गोंदिया में 13.6 मिमी, आमगांव में 8.1 मिमी, तिरोड़ा में 11.6 मिमी, सालेकसा में 10.8 मिमी, देवरी में 8.5 मिमी, अर्जुनी मोरगांव में 3.7 मिमी तथा सड़क अर्जुनी तहसील में 7.7 मिमी बारिश रिकार्ड की गई। अगस्त माह में 1 अगस्त से 29

अगस्त तक 259.9 मिमी बारिश जिले में रिकार्ड की गई है, जबकि इस अवधि में सामान्य मानसून में 387.2 मिमी बारिश अपेक्षित होती है। अर्थात् अगस्त माह में अब तक अपेक्षित बारिश की तुलना में केवल 67.1 प्रतिशत बारिश ही हुई है। यानी 33 प्रतिशत बारिश कम हुई है। फिर भी स्थिती को संतोषजनक माना जा रहा है।

कवलेवाड़ा में रक्षाबंधन पर अनूठी पहल

जवानों को राखी बांधकर किया देशसेवा को सलाम

पेड़ों को राखी बांध दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

संवाददाता / तिरोड़ा

रक्षाबंधन के अवसर पर जिला परिषद उच्च प्राथमिक विद्यालय, कवलेवाड़ा में विद्यार्थियों द्वारा एक अनूठा, प्रेरणादायी एवं संस्कारपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर वर्तमान में पुलिस विभाग, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) तथा भारतीय सेना में देशसेवा कर रहे जवानों का विद्यार्थिनियों ने राखी बांधकर सम्मान किया और उनके राष्ट्रसेवा के कार्य को नमन किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विद्यालय परिसर में स्थित पेड़ों को भी राखी बांधी। इसके माध्यम से ‘वृक्ष ही जीवन हैं’ तथा पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश दिया गया। जवानों को राखी बांधकर जहां देश की सुरक्षा में उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई, वहीं पेड़ों को राखी बांधकर प्रकृति के संरक्षण



का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि तिरोड़ा पुलिस विभाग के थाना प्रभारी अमित वानखेडे सहित देशसेवा में कार्यरत जवानों का विद्यार्थियों ने राखी बांधकर सम्मान किया। कार्यक्रम का अध्यक्षता जिला परिषद सदस्य किरण कुमार पारधी ने की। प्रमुख अतिथि के रूप में सरपंच इंदूताई पारधी उपस्थित थीं। इस अवसर पर विद्यालय की मुख्याध्यापिका

संगीता गुणीलाल ठाकरे, समस्त शिक्षकवृंद, शाला प्रबंधन समिति के पूर्व अध्यक्ष बबलदास भाऊ ठाकरे, अजय बारापात्रे, देवेंद्र चौधरी, खुमैंद्र राहंगडाले, पुलिस विभाग के अधिकारी एवं जवान तथा बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित मान्यवरों ने विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति समर्पण, स्वावलंबन, अनुशासन, आपसी प्रेम, मानवता और देशसेवा के

महत्व के बारे में मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के प्रेम का पर्व नहीं, बल्कि विश्वास, सुरक्षा, कर्तव्य और जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। इस अवसर पर ‘जवानों को राखी-देशसेवा को सलाम’ और ‘पेड़ों को राखी-पर्यावरण संरक्षण का संकल्प’ जैसे संदेशों के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम एवं पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित की गई। विद्यालय में आयोजित यह पहल विद्यार्थियों के मन में संस्कारों के बीज बोने के साथ-साथ समाज, प्रकृति और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना मजबूत करने वाली साबित हुई। कार्यक्रम ने रक्षाबंधन के पर्व को सामाजिक सरोकार और राष्ट्रसेवा की भावना से जोड़ते हुए एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया।

बनगांव पीएचसी के स्थानांतरण का नागरिकों ने जताया विरोध

कहा, स्थानांतरण नहीं सुविधाएं चाहिए

संवाददाता / गोंदिया

आमगांव तहसील मुख्यालय में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनगांव को सितेपार ग्राम में स्थानांतरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बात का पता चलते ही बनगांव नागरिकों में तीव्र असंतोष निर्माण हो गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही आम नागरिकों ने भी इस केंद्र के स्थानांतरण का तीव्र विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि पीएचसी का स्थानांतरण करने के बजाए यहां सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

आमगांव शहर के हृदयस्थल में यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 50 वर्षों से स्थित है और यहां आज भी 250 से 300 मरीज प्रतिदिन आते हैं। इमारत पुरानी हो जाने के कारण यहां कुछ समस्याएं निर्माण हुई हैं। नागरिकों ने इस पीएचसी को यहां से स्थानांतरित किए जाने की बजाय यहां पर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। इस संबंध में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. अभिजित गोल्हार से विस्तृत जानकारी मांगने पर उन्होंने बताया कि शासन के नियमानुसार जहां पर सरकारी स्वास्थ्य सेवा अपग्रेड होती है, वहां पीएचसी की आवश्यकता नहीं है। चूंकि आमगांव में अब ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र है, जो लगभग 20 वर्ष पूर्व शुरू किया गया है।



नियमानुसार उसी समय आमगांव पीएचसी को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाना चाहिए था, लेकिन जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों की मांग एवं भावनाओं को देखते हुए आमगांव पीएचसी को बनगांव का नाम देकर उसी जगह कायम रखा गया। वर्तमान में वहां की इमारत जर्जर हो गई है और शासन के नियमानुसार पीएचसी के नवनिर्माण के लिए उस स्थान पर मंजूरी मिलना संभव नहीं है। पीएचसी की रुपण कल्याण समिति ने भी एक प्रस्ताव पारित कर जिला परिषद स्वास्थ्य विभाग को भेजा था। बाद में जिला परिषद की स्थायी समिति के सभा में भी यह मामला सामने आने पर इस पीएचसी को सितेपार में स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। लेकिन नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों की मांग एवं भावनाओं को देखते हुए फिलहाल इस मामले को स्थगित रखा गया है।

जाहिरनामा

प्रस्तुत जाहिरनाम्याव्दरे सर्व जनतेला सुचित करण्यात येते की श्रीमती. सुशिला राजेंद्र मेश्राम मौजा आष्टी, ता. तुमसर जि. भंडारा यांच्या स्वतःची जन्माची नोंद दिनांक 15/11/1972 रोजी नगर परिषद तिरोडा, ता. तिरोडा, जि. गोंदिया. येथे झालेली नाही. त्यामुळे शासकिय कामा करीता त्यांना जन्म प्रमाणपत्राची आवश्यकता असल्यामुळे यांनी आपले स्वतःचे जन्म दिनांक 15/11/1972 ची नोंद नगर परिषद तिरोडा, ता. तिरोडा, जि. गोंदिया येथील रेकार्डवर घेण्याचा आदेश मिळण्याबाबत जन्म/मृत्यु नोंदणी अधिनियम 1969 चे कलम 13 (3) अंतर्गत अर्ज सादर केला आहे.

सबब अर्जदार नामे श्रीमती. सुशिला राजेंद्र मेश्राम मौजा-आष्टी, ता. तुमसर जि. भंडारा यांच्या स्वतःची जन्माची नोंद दिनांक 15/11/1972 नगर परिषद तिरोडा, ता. तिरोडा, जि. गोंदिया. येथे करण्याच्या संबंधात कोणाचेही दावे हरकती किंवा हितसंबंध असल्यास त्यांनी आपले दावे/हरकती अर्ज दिनांक 23/08/2026 च्या आत लेखी स्वरूपात तहसिल कार्यालया तिरोडा या कार्यालयास सादर करावे त्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या आक्षेप हरकतीचा विचार केला जाणार नाही. याची कृपया नोंद घ्यावी.

स्वा/-
तहसिलदार तिरोडा